

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 3990-दो/2015 निगरानी - विरुद्ध- आदेश दिनांक
14-10-2015 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,
ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 18/2013-14 अपील

महिला भागो पत्नि स्व. किशनलाल
(मृतक वारिस)

- 1- हाकिम 2- मोतीलाल 3- महेश
- 4- दीना पुत्रगण स्व. किशनलाल
- 5- मालती नावालिक पुत्री स्व.किशनलाल
- 6- रामचरण पुत्र बल्लू जाटव
- 7- मुन्नी पुत्री बल्लू जाटव

8- मायाराम 9- परसादीलाल पुत्रगण श्यामा जाटव
सभी निवासी ग्राम सीहोर तहसील नरबर जिला शिवपुरी
विरुद्ध

—आवेदकगण

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

—अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस०पी०धाकड़)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री राजीव शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 18-4-2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण
क्रमांक 18/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-15 के विरुद्ध म.प्र.
भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि स्वर्गीय श्रीमती भागो पत्नि स्व. किशनलाल
ने तहसीलदार करैरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम सीहोर
स्थित भूमि सर्वे नंबर 4175 रकबा 1-2010 एवं 1825 रकबा 0.080 हैक्टर
तथा 1826 रकबा 0.350 हैक्टर रहे हैं। यह सर्वे नंबर बंदोवस्त के पूर्व के है
जो सर्वे नंबर 1679 रकबा 1-818 से निर्मित है सर्वे नंबर 1827/2 रकबा
0.18 है. भूलवश शासकीय अंकित कर दिया था जिसकी दुरुस्ती हेतु प्रकरण
क्रमांक 22/1999-2000 अ-5 चला था एवं आदेश दिनांक 25-9-2000 से

अभिलेख दुरुस्ती के आदेश हुये है परन्तु पटवारी अभिलेख में अमल नहीं कराया गया। आदेश दिनांक 25-9-2000 का अमल कराया जावे। तहसीलदार करैरा ने प्रकरण क्रमांक 57 बी 121/11-12 पंजीबद्ध किया तथा जांच एवं सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 25-2-12 पारित करके स्वर्गीय श्रीमती भागो का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, करैरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, करैरा ने प्रकरण क्रमांक 198/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-8-13 से अपील अस्वीकार कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 18/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-15 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि मृत महिला भागो पत्नि स्व. किशनलाल ने अपने तहसीलदार करैरा को आवेदन दिनांक 19-9-11 प्रस्तुत कर मांग की है कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-9-2000 के अनुसार शासकीय अभिलेख में दुरुस्ती की जावे। आवेदिका का यह आवेदन आदेश दिनांक 25-9-2000 के 11 वर्ष के अंतराल से है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आदेश दि. 14-10-15 में निकाले गये निष्कर्षों के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश में विवेचना कर निष्कर्ष दिया है कि -

आवेदक/अपीलार्थी के द्वारा संहिता की धारा 89 के अंतर्गत बंदोवस्त त्रुटि हेतु आवेदन दिनांक 7-6-2000 को प्रस्तुत किया गया है। तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 25-9-2000 को संशोधन के आदेश दिये गये हैं। म०प्र०राजपत्र दिनांक 18 अप्रैल 2003 के द्वारा संहिता की धारा 89 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ तहसीलदार को प्रदान की गई है। तहसीलदार को वर्ष 2000 में धारा 89 के अंतर्गत कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं थी इसलिये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-9-2000 अधिकारिता रहित होकर शून्यवत् है।

स्पष्ट है कि जब तत्समय अर्थात् वर्ष 2000 में धारा 89 के अंतर्गत तहसीलदार को बंदोवस्त त्रुटियों को सुधार करने के अधिकार नहीं थे, तत्का. तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/99-2000 अ-5 में पारित आदेश दिनांक 25-9-2000 अधिकारितारहित होने से ऐसे आदेश का अमल संभव ही नहीं है जिसके कारण तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 57 बी 121/11-12 में पारित आदेश दिनांक 25-2-12 एवं अनुविभागीय अधिकारी, करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 198/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-8-13 तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-15 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिनमें हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-10-15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।


(एस०एस०अली)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर